



गर्म होते आर्कटिक के कारण स्थानीय वन्य जीवों के लिए खतरा बहुत बढ़ गया है, इनमें प्रमुख हैं मस्क ऑक्स (कस्तूरी बैल)। वैज्ञानिकों ने एक शोध में पाया कि मस्क ऑक्स जिंदा रहने के लिए जूझ रहे हैं और इनके लिए सबसे बड़ा संकट भोजन का है। हालांकि ये जीव बहुत थोड़े से भोजन पर भी जी लेते हैं, पर वो भी इन्हें नहीं मिल पा रहा है, कारण है ग्लोबल वॉर्मिंग। असल में सर्दी में जब उत्तरी ग्रीनलैण्ड में बर्फ होती है तो मस्क ऑक्स भोजन की तलाश में दक्षिणी भाग में चले जाते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लोबल वॉर्मिंग के कारण ग्रीनलैण्ड में गर्मियों में ज्यादा गर्मी, बरसात में ज्यादा बारिश और सर्दी में ठंड और ज्यादा पड़ने लगी है, जिसकी वजह से उत्तरी भाग में बर्फ ज्यादा हो गई है, खासकर ठोस बर्फ, जिसके कारण ये पशु दक्षिण में नहीं जा पा रहे हैं, ऐसे में उनके बच्चों के भूखे मर जाने का खतरा बढ़ रहा है। वहीं, गर्मी में मस्क ऑक्स उत्तर की तरफ जाते हैं, लेकिन ग्लोबल वॉर्मिंग के कारण तापमान ज्यादा बढ़ रहा है, ऐसे में वे उत्तर दिशा में और आगे तक जा तो सकते हैं पर अन्ततः आर्कटिक के अंतिम उत्तरी छोर पर पहुँचने के बाद उनके पास जाने के लिए जगह नहीं बचेगी। डैनमार्क के वैज्ञानिकों की एक टीम ने मस्क ऑक्स का अध्ययन करने के लिए ग्रीनलैण्ड की यात्रा की थी, जिसमें उन्होंने मस्क ऑक्स को नाक से ठोस बर्फ को तोड़ने की असफल कोशिश करते देखा, ताकि बर्फ में दबी घास खा सकें। टीम के सदस्य कार्स्टन प्रोन्डाल ने कहा कि "ये बैल ढीली पाउडर जैसी बर्फ को तो हटा देते हैं पर उत्तरी ग्रीनलैण्ड में ठोस बर्फ ज्यादा है जिसे वो हटा नहीं पाते।" शोधकर्ताओं ने कहा कि "हमारे जाकनबर्ग रिसर्च स्टेशन के आसपास ही गत 20 सालों में आर्कटिक की जलवायु में काफी बदलाव आया है। गर्मी के मौसम में तापमान तीन से छः डिग्री तक बढ़ गया है। तापमान बढ़ने का अर्थ है कि इस क्षेत्र में नए परजीवी पनप सकते हैं, बीमारियाँ फैल सकती हैं। कैंडेडा में तो मस्क ऑक्स में एक नई बीमारी भी देखी गई है। जलवायु परिवर्तन के कारण इस प्रजाति पर दबाव बढ़ता जा रहा है और यह विलुप्ति के कारगर पर पहुंच रही है।"

महंगाई के खिलाफ होने वाली देशव्यापी रैली की तैयारियों को परखने माकन आएंगे जयपुर

मंगलवार दोपहर 2 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर बैठक होगी

जयपुर, 29 नवम्बर (का.प्र.)। महंगाई के खिलाफ अभियान को गति देने के लिए कांग्रेस पार्टी 12 दिसंबर को दिल्ली में देशव्यापी विशाल रैली करने जा रही है। रैली में जहां देश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता शामिल होंगे तो इसे सफल बनाने के लिए राजस्थान को भीड़ जुटाने की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। वैसे भी मंत्री पद से हटने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के पास

अब संगठन की जिम्मेदारी बची है। अतः अब वे दिल्ली रैली को सफल बनाने के लिए पूरा समय दे रहे हैं। राजस्थान की सीमाएं दिल्ली से जुड़ी हैं। ऐसे में इस महंगाई के खिलाफ होने वाली रैली में प्रदेश से कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा उम्मीद है। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी इसे लेकर सक्रिय हो गई है और इस रैली को सफल बनाने के लिए राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ ही मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के साथ चर्चा कर चुके हैं।

रैली की तैयारियों को परखने के लिए राजस्थान के प्रभारी महासचिव अजय माकन भी मंगलवार को जयपुर आ रहे हैं। वे इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस

मुख्यालय पर बैठक लेंगे।

इस रैली की सफलता सरकार और संगठन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रैली के 2 सप्ताह पहले मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठकर रैली को सफल बनाने का आह्वान मीडिया के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कर चुके हैं। अब इसी कड़ी में राजस्थान प्रदेश प्रभारी अजय माकन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में दिल्ली में होने वाली बैठक को सफल बनाने के लिए मंत्रियों, विधायकों, विधायक प्रत्याशियों,

सांसद प्रत्याशियों, पीसीसी पदाधिकारियों और निवर्तमान जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है। मंगलवार को दोपहर 2 बजे होने वाली इस बैठक के जरिए इन सभी नेताओं के साथ राजस्थान कांग्रेस के तीनों प्रमुख नेता ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को ले जाने का रोड मैप तैयार करेंगे।

वैसे भी दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की रैलियों में राजस्थान हरियाणा उत्तर प्रदेश और पंजाब पर ही सबसे ज्यादा भीड़ ले जाने का दायरेदार रहता आया है क्योंकि यह तमाम प्रदेश दिल्ली से नजदीक पड़ते हैं। यही कारण है कि राजस्थान से रैली में 30-35 हजार लोगों को ले जाने की तैयारियों की जा रही है।

दोनों सदनों ने पांच-पांच मिनट दिये कृषि विधेयकों को

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 29 नवम्बर। चार सप्ताह चलने वाला संसद का शीतकालीन बड़े हंगामे, उतेजना एवं क्षोभ में शुरू हुआ तथा पहले लोकसभा

खड़गे राज्यसभा में, विधेयकों के पक्ष में दिये गये धरनों में 700 किसानों की मृत्यु की बात शुरू कर ही रहे थे कि, राज्यसभा के उपसभापति ने टोक कर बस को रूकवाया।

में तथा उसके बाद राज्यसभा में वह विधेयक, किसी तरह की चर्चा कराये बिना, पाँच-पाँच मिनट में पारित हो, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राजस्थान का "साइड शो" लखनऊ में

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 29 नवम्बर। उत्तर प्रदेश की बड़ी चुनावी लड़ाई में राजस्थान का कोण भी जुड़ गया है। मरू-प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के एक गुप ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया है तथा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी

वाड़ा से भेंट करने की माँग की है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले जयपुर में इस महीने के शुरू में 47 दिवसीय विरोध-प्रदर्शन कर चुका है। गुप की माँग थी कि उन रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाये, जिनकी भर्ती हेतु राजस्थान सरकार परीक्षाएं आयोजित कर चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विरोध प्रदर्शन कर रहे इन युवाओं से समझौता-वार्ता करने अपने नवनियुक्त सलाहकार दानिश अबरार को भेजा था, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला तथा इस गुप ने 23 नवम्बर को अपना धरना-स्थल

लखनऊ को बना लिया। जाहिर है कि यह घटना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिये परेशानी का कारण बन गई है, जो पार्टी की अंदरूनी खींचतान के कारण लम्बे समय से परेशान चल रहे हैं। मुख्यमंत्री इस कदम को उनके "राजनैतिक विरोधियों द्वारा प्रेरित कदम" मान रहे हैं। गहलोत का

उन्हें नौकरी दी भी जाती है तो ये नौकरी लेंगे नहीं, क्योंकि उनमें से कुछ लोग तो राजनीति में जाना चाहते हैं। प्रियंका गांधी वाड़ा को उत्तर प्रदेश के युवाओं में तवज्जो मिलती रही है। कांग्रेस ने सता में आने की स्थिति में राज्य में 20 लाख नौकरियों देने का वादा भी किया है। उक्त महासंघ के

कहना है कि राजस्थान में सभी राज्यों से ज्यादा नौकरियाँ दी गई हैं। आंदोलन-स्थल के रूप में लखनऊ का चयन करने का उनका कदम आश्चर्य क्या बताता है? गहलोत ने आगे कहा कि युवाओं के इस गुप की रूचि नौकरियों से कहीं ज्यादा राजनीति में है। "उन्होंने कहा, "अगर

बेरोजगार युवकों ने लखनऊ में धरना दिया, प्रियंका गांधी से मिलने के लिये।

अटपटी स्थिति बनती देख, मु. मंत्री ने सलाहकार दानिश अबरार को जिम्मेवारी सौंपी, इन युवकों से बातचीत करने के लिये।

आंदोलनकारियों का मानना है कि वाड़ा उनकी बात को ध्यान से सुनेंगी। इससे पूर्व यह गुप विरोध-प्रदर्शन की अभिनव रणनीतियाँ अपना चुका है, जिनमें शामिल हैं- कमीज उन्नाहर प्रदर्शन करना, राज्य के मंत्रियों को गुलाब के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

यू-टर्न से सभी खुश नहीं सरकार में

-रेणु मिश्रल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 29 नवम्बर। संसद सत्र का पहला दिन कृषि कानूनों को वापस लिये जाने तथा मोदी सरकार द्वारा हमला किये जाने के नाम रहा। सरकार ने तीनों कृषि कानून बिना किसी चर्चा के वापस ले लिये तथा विपक्ष को जबरदस्ती खामोश कर दिया। विपक्ष इन कानूनों तथा उन किसानों की

इन लोगों को शिकायत है कि, पहले तो पार्टी ने सभी भाजपा सांसदों को, इन विधेयकों के पक्ष में, "डिफेंस" में पूरा जोर लगाने के लिये कहा और फिर बिना बहस के ही कानून वापस ले लिये गये।

तुर्दशा पर बहस करना चाहता था, जो पिछले सवा साल से सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। इसके शीघ्र बाद ही, राज्यसभा के सभापति ने कांग्रेस, टी.एम.सी. तथा शिवसेना के 12 विपक्षी सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया। शीतकालीन आज ही शुरू हुआ था। यह निलम्बन मानसून सत्र के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बिना बहस के कृषि कानून वापस लिये गये संसद में

साथ ही पिछले मानसून सत्र में सदनों में हाथापाई, महिला मार्शल के साथ अभद्रता आदि "अपराधों" के कारण राज्यसभा के बारह सांसद निलंबित किये गये

विपक्ष ने भी पलटवार में सरकार पर आरोप लगाया कि, चुनाव की दृष्टि से चयन करके सांसदों को निलंबित किया गया है। उदाहरण के लिये आप पार्टी के संजय सिंह को निलंबित नहीं किया गया, हालांकि हंगामे के वीडियो में संजय सिंह को हाथ में काला झण्डा लेकर राज्यसभा सचिवालय के स्टाफ की टेबलों पर चढ़कर नाचते हुए साफ देखा जा सकता है। सरकार आप पार्टी के सांसद को हीरो नहीं बनाना चाहती थी, पंजाब के चुनाव में।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि, तृणमूल कांग्रेस ने संयुक्त विपक्ष के उस पत्र पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया, जिसमें विपक्ष की पार्टियों का, कल बैठक कर, सांसदों के निलंबन पर रणनीति तय करने के लिये मंथन करने का आह्वान किया गया है।

विपक्ष में यह भी चर्चा का विषय है कि, जिस रूल के तहत इन सांसदों को निलंबित किया गया है, उसमें साफ लिखा है कि, सांसद का निलंबन केवल संसद के शेष "पीरियड" के लिये ही हो सकता है और हंगामे की घटना पिछले सत्र की है।

लेकिन, इस पत्र पर तृणमूल कांग्रेस ने हस्ताक्षर नहीं किया, तृणमूल कांग्रेस विपक्ष की मीटिंग में भी शामिल नहीं हो रही है। पूर्ववर्ती सत्र में किये गये काम के लिये, नए सत्र में सांसदों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का अब तक कोई पूर्वोदाहरण नहीं है। नियम 256, जिसके तहत वे निलम्बित किये गये हैं, कहता है कि किसी सांसद को "उस अवधि के लिये निलम्बित किया जा सकता है, जो उस सत्र की शेष अवधि

से ज्यादा न हो।" इस नियम का उल्लेख करते हुये, राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा ने कहा कि अगर यह निलम्बन वापस नहीं लिया गया तो विपक्ष पूरे शीतकालीन सत्र का बहिष्कार करेगा। अस्त-व्यस्त स्थिति में चला मानसून सत्र, जिसमें "पैगस स्याई वेअर" के मुद्दे पर चर्चा की माँग को लेकर सरकार और विपक्ष में तनातनी चल रही थी, स्तब्ध कर देने वाली उग्रता तथा महिलाओं की हाथापायी के आरोपों के बीच 11

अगस्त को समाप्त हुआ था। सदन की स्थिति विस्फोटक हो गई थी, क्योंकि जनरल इन्वोर्नेन्स बिजनैस (नैशनलाइजेशन) अमेंडमेंट बिल को प्रवर समिति को सौंपे जाने की मांगों के बावजूद, इस विधेयक को पारित कर दिया गया था। सदन की कार्यवाही की सी.सी.टी.वी. फुटेज, विपक्षी सदस्यों को राज्यसभा के अंदर सुरक्षाकर्मियों से हाथापाई करते हुये दिखा रही हैं। काले झंडे लिये हुये सांसद मेजों पर चढ़े हुये तथा फाइलों तथा कागजातों को बिखेरते

हुये दिखाई दे रहे थे। जहाँ सरकार ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि उसने महिला मार्शलों से हाथापाई की, वहीं विपक्ष ने एक संयुक्त बयान में आरोप लगाया कि "विपक्षी नेताओं तथा सदस्यों, जिनमें महिला सांसद भी शामिल थीं, से हाथापायी करने के लिये" बाहरी लोग "अंदर लाये गये थे।" सरकार ने विपक्ष के इन दावों का खंडन किया कि "बाहरी लोग" अंदर लाये गये थे, तथा अन्ततः इस मामले को जाँच के लिये सांसदों की एक विशेष

कमेटी को सौंप दिया गया था। लेकिन कांग्रेस इस प्रकार की किसी भी कमेटी से अलग रही थी तथा उसने कहा था कि जाँच के जरिये सांसदों को डरा-धमका कर खामोश करने की कोशिश समाहित रहेगी। राज्यसभा की सिक्वोरिटी रिपोर्ट का कहना है कि एक सांसद ने हाथापाई की थी तथा "एक पुरुष मार्शल का गला बुरी तरह दबा दिया गया तथा सुरक्षा घेरे को तोड़ने के उद्देश्य से उसे अंदर घसीट लाया गया था।" रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि महिला सांसदों ने एक महिला मार्शल को "खींचा तथा घसीटा" था तथा सदन के "वैल" में उस पर हमला बोला था।

किसान पिछले एक वर्ष से जिन तीन कृषि बिलों को लेकर दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन करते आ रहे थे, उन्हें रद्द करने के प्रति बहुत कम आदरभाव दर्शाया गया। संसद के सोमवार के मिनिट्स पर गौर कीजिए। लोकसभा में सुबह पारित किए गए विधेयक को दोपहर के भोजन के बाद राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही पारित कर दिया गया। विपक्ष ने सरकार की कटघरे में खड़ा करने की कोशिश में जो कि इन विधेयकों को वापस लेकर पहले ही बैकफुट पर है, बहस की माँग की थी। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से दो दिसम्बर तक जवाब मांगा कि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कन्स्ट्रक्शन पर लगाये गये प्रतिबंध के बावजूद निर्माण कार्य कैसे जारी है।

समक्ष दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान समने आया। यह याचिका दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली के एक 17 वर्षीय छात्र ने दायर की थी। कोर्ट (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'सैन्ट्रल विस्टा' का निर्माण क्यों'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 29 नवम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केन्द्र सरकार से कहा कि वह देश की राजधानी में निर्माण कार्य पर 24 नवम्बर को लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद सैन्ट्रल विस्टा में जोर-शोर से चल रहे निर्माण कार्य के बारे में अगली सुनवाई तिथि 2 दिसम्बर तक स्थिति स्पष्ट कराए। यह मामला चोफ जस्टिस ऑफ इण्डिया (सी.जे.आई.) एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली एक विशेष बेंच के

समक्ष दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान समने आया। यह याचिका दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली के एक 17 वर्षीय छात्र ने दायर की थी। कोर्ट (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

